मुख्य समाचार :–

- मार्च में वस्तु और सेवा कर संग्रह 8 दशमलव 8 प्रतिशत बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये से अधिक हुआ।
- 'वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम' के तहत आईटीबीपी और उत्तराखंड औद्यानिक परिषद के बीच समझौता। प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत।
- गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के गेट खुले। पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग सीजन शुरू।
- प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026–27 की शुरुआत। पौड़ी और चमोली में छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गईं।

जीएसटी संग्रह

इस वर्ष मार्च में कुल वस्तु और सेवा कर –जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 8 दशमलव 8 प्रतिशत बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। मार्च 2025 में कुल जीएसटी राजस्व एक लाख 83 हजार करोड़ रुपये से अधिक रहा। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष मार्च में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 40 हजार 549 करोड़ रुपये और राज्य जीएसटी संग्रह 53 हजार 268 करोड़ रुपये रहा। एकीकृत जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इस बीच, वित्त वर्ष 2025–26 में सकल जीएसटी राजस्व बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष के 20 लाख करोड़ रुपये से 8 दशमलव 3 प्रतिशत अधिक है।

आईटीबीपी समझौता

'वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम' के अंतर्गत भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल– आईटीबीपी और उत्तराखंड औद्यानिक परिषद के बीच आज मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत राज्य में तैनात आईटीबीपी की वाहिनियों को स्थानीय स्तर पर ताजे फल और सब्जियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समझौता ज्ञापन को राज्य के किसानों, स्थानीय उत्पादकों और सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे जहां जवानों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी, वहीं प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल "स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा" देने के राज्य सरकार के संकल्प को सशक्त करेगी और किसानों को अपनी उपज के विपणन के लिए एक सुदृढ़ व स्थायी मंच प्रदान करेगी। इस व्यवस्था के तहत चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ ही देहरादून में भी स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। गौरतलब है कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच स्थानीय उत्पादों की खरीद के लिए पहले भी समझौता किया गया है, जिसके काफी अच्छे परिणाम रहे हैं। अभी तक आईटीबीपी 14 करोड़ रुपये से अधिक के स्थानीय उत्पादों की खरीद कर चुकी है, जिसे और बढ़ाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में आईटीबीपी, वार्षिक मांग की 25 प्रतिशत फल और सब्जियां भी खरीदती है, तो इससे स्थानीय किसानों को लगभग 6 करोड़ रुपये की आमदनी होगी।

मुख्य सचिव

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने आज सचिवालय में स्टेट प्रगति पोर्टल की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा संचालित राज्य व केंद्रपोषित महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा स्टेट प्रगति पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। उन्होंने विभागों को अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को पोर्टल में शीघ्र अपलोड करने को कहा। मुख्य सचिव ने कहा कि विभागों को अपनी योजनाओं के विभिन्न स्तर निर्धारित करने होंगे, ताकि धीमी प्रगति वाली योजनाओं पर नजर रखी जा सके। इससे योजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने पोर्टल में सभी विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार की सभी योजनाओं को भी शामिल किए जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से अब तक कितना रोजगार उत्पन्न कर पाए हैं, इसका विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने इसके लिए नियोजन विभाग को सभी विभागों की स्वरोजगार से सम्बन्धित योजनाओं का पिछले 3 से 5 सालों का विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि योजनाओं की समीक्षा हो सके और उसकी खामियों को समझकर दूर किया जा सके। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने स्टेट प्रगति पोर्टल का ट्रायल लेते हुए विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली।

गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क

उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के गेट आज पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में ट्रैकिंग और पर्यटन गतिविधियों की औपचारिक शुरुआत हो गई है। पिछले साल 30 नवंबर को पार्क के गेट बंद कर दिए गए थे। पार्क प्रशासन के अनुसार अब पर्यटक निर्धारित नियमों के तहत पार्क में प्रवेश कर सकेंगे। खासतौर पर विश्व प्रसिद्ध गौमुख ट्रैक के लिए परमिट जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पार्क के उप निदेशक हरीश नेगी ने बताया कि पार्क में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटकों को पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

भौक्षणिक सत्र

प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज शैक्षणिक सत्र 2026–27 की शुरुआत उत्साह और उमंग के साथ हुई। इसी कड़ी में पौड़ी जिले में प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट तक सभी राजकीय विद्यालयों में प्रवेश उत्सव के तहत छात्र–छात्राओं का स्वागत किया गया और उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गईं। इस बार विशेष पहल के तहत सत्र के पहले दिन ही विद्यार्थियों को नई पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई, जिससे पढ़ाई का क्रम बिना किसी देरी के प्रारंभ हो सके। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय संख्या पांच, पौड़ी में जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने नन्हें विद्यार्थियों को पुस्तकें वितरित करते हुए उनसे आत्मीय संवाद किया और उनके भविष्य को लेकर उत्साहवर्धन किया। उधर, चमोली जिले के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोपेश्वर में निःशुल्क पुस्तक वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने छात्रों को पुस्तकें वितरित करते हुए नए शैक्षणिक सत्र की शुभकामनाएं दीं। नई किताबें पाकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला।

सीवरेज / निर्देश

हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नगर क्षेत्र में सीवरेज निर्माण कार्यों को चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने श्रमिकों की संख्या बढ़ाने और कार्य को तीन शिफ्टों में कराने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को दिए हैं। जिलाधिकारी ने आज सीवरेज निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से अपर रोड पर चल रहे सीवरेज निर्माण कार्यों को एक सप्ताह के भीतर हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए।

नगर निगम देहरादून

नगर निगम देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर भूमि अनुभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए है। इस संबंध में आयोजित बैठक में उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों से पिछले एक वर्ष में अतिक्रमण मुक्त कराई गई नगर निगम की जमीनों का पूरा विवरण प्रस्तुत करने को कहा। महापौर ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि नगर निगम की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने–अपने वार्डों में सतर्कता बनाए रखें और भू–माफिया द्वारा किसी भी प्रकार के कब्जे को तुरंत चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करते हुए भूमि को तत्काल मुक्त कराया जाए। महापौर ने यह भी कहा कि पार्षदों द्वारा प्राप्त अतिक्रमण संबंधी शिकायतों पर बिना किसी देरी के त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और प्रत्येक मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए।